शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 26 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 17 – 24 जून 2024 मूल्य पांच रूपये

क्या यह उपचुनाव मुद्दों की जगह आरोपों–प्रत्यारोपों पर लडा जायेगा?

आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री को सबसे बड़ा माफिया करार दिया

फरवरी 2023 में खनन पॉलिसी में बदलाव भाई को लाभ पहुंचाने के लिये किया गया

कांगड़ा बैंक के ऋण मुआफी के मुद्दे उछलने की संभावना

क्या नादौन में एचआरटीसी द्वारा खरीदी जमीन विलेज कामन लैण्ड है?

शिमला/शैल। क्या यह उपचुनाव मुद्दों पर सवाल पूछने और बहस उठाने की बजाये आरोपों और प्रत्यारापों के तीखे पन पर लड़ा जायेगा? यह सवाल इसलिये प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री और पूरी कांग्रेस पार्टी भाजपा द्वारा धन-बल के सहारे सरकार गिराने का प्रयास करने को अब भी केंद्रीय मुद्दा बनाकर जनता में उछाल रहे हैं। इस आरोप के खुलासे में उन सारे विधायकों को जिनके क्रॉस वोटिंग करने से राज्यसभा चुनाव में भाजपा के हर्ष महाजन कांग्रेस के बराबर वोट हासिल करके पर्ची सिद्धांत पर जीत गये। यह सही है कि जब भाजपा के अपने 25 ही विधायक थे तो वह वोटिंग में 34 कैसे हो गये। यहां क्रॉस वोटिंग करने वालों को बिकाऊ विधायक लोकसभा चुनाव में प्रचारित किया गया। लेकिन इस प्रचार से भाजपा चारों सीटें जीत गयी। विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस छः में से चार सीटें जीत गयी। इस जीत को मुख्यमंत्री में जनता के विश्वास की संज्ञा दी गयी। लेकिन इस विश्वास पर उस समय एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया जब मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र नादौन में कांग्रेस को बढ़त नहीं दिला पाये। उपचुनावों में चारों सीटें जीतने को अधिकांश में भाजपा की आंतरिक राजनीति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बल्कि प्रदेश की चारों सीटें जीतने के बाद भी अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्री परिषद में स्थान न मिल पाना भी इसी राजनीति का प्रतिफल माना जा रहा है।

इस परिदृश्य में हो रहे हैं इन उपचुनावों में फिर मुख्यमंत्री ने विधायकों को बिकाऊ होने के आरोप को उछाल दिया है। इसी बिकाऊ के आरोप के साथ ही खनन माफिया और भू-माफिया के टैग में भी इनके साथ जोड़ दिए गये हैं। पिछली बार धर्मशाला में सुधीर शर्मा को मुख्यमंत्री ने भू-माफिया की संज्ञा देते हुये उनकी कुछ संपत्तियों के नाम मीडिया में उछाले थे लेकिन उनके कोई दस्तावेजी प्रमाण जारी नहीं कर पाये थे। इन आरोपों के जवाब में सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप दस्तावेजी प्रमाणों के साथ लगाये। सुधीर के आरोपों के सामने मुख्यमंत्री द्वारा लगाये गये आरोप हल्के पड़ गये और परिणाम स्वरूप सुधीर शर्मा चुनाव जीत गये। इसी तरह बड़सर में पैसे मिलने का एक आरोप उछाला गया। मुख्यमंत्री ने यह कथित पैसे लखनपाल के नाम लगा दिये। पैसे मिलने के आरोप का जिस आक्रमकता के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जवाब दिया और प्रति प्रश्न किये तब मुख्यमंत्री का आरोप कमजोर पड़ गया और लखनपाल जीत गये।

पिछले उपचुनाव ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जिसने तीव्र आक्रामकता अपनायी उसकी जीत हुई है। अब इन उपचुनावों में भी मुख्यमंत्री के पास वही पुराना राग है। बिकाऊ और धनबल का लेकिन आज तक इस आरोप का कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण जनता के सामने नहीं ला पाये हैं। हमीरपुर से पूर्व निर्दलीय विधायक और अब भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री को ही सबसे बड़ा माफिया होने का आरोप लगा दिया है। आशीष शर्मा ने खुलासा किया है कि दिसम्बर 2022 में सुक्खू सरकार बनने के बाद फरवरी 2023 में प्रदेश की खनन पॉलिसी बदल दी गयी। आशीष के मुताबिक यह बदलाव अपने सगे भाई को लाभ पहुंचाने के लिये किया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से इस आरोप का कोई जवाब नहीं आया है। पीछे जब सुधीर शर्मा ने नादौन में ढाई लाख में खरीदी गई जमीन को एचआरटीसी द्वारा करीब पौने सात करोड़ में खरीद लेने का जो आरोप लगाया था माना जा रहा है कि उसके पूरे दस्तावेज इस चुनाव में सामने आएंगे। इस खरीद-बेच में बड़ा सवाल तो यह उठा था कि यह जमीन बिक कैसे गयी? इसकी रजिस्ट्री हो कैसे गयी? चर्चा है कि जहां पर यह एचआरटीसी द्वारा खरीदी गई जमीन है वहीं पर 1974 में भू-दान आन्दोलन यज्ञ के नाम पर राजा नादौन की 1224 कनाल जमीन को लैण्ड सीलिंग से बाहर रखा गया था। उस समय राजा नादौन की एक लाख कनाल से अधिक जमीन विलेज कामन लैण्ड हो गयी थी। इस विलेज कामन लैण्ड को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। इसी तर्ज पर भू-दान आन्दोलन यज्ञ के नाम पर हुई जमीनों को भी खरीदा बेचा नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि शायद एचआरटीसी द्वारा खरीदी गई जमीन भी शायद विलेज कामन लैण्ड है।

इस उपचुनाव में आरोपों और प्रत्यारोपों के हथियार ही इस्तेमाल होंगे। यह आशीष शर्मा के ब्यान से स्पष्ट हो जाता है। फिर इस बार तो पिछले चुनाव के अंतिम दिनों में कांगड़ा सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक के करोड़ों की ऋण माफी को लेकर वायरल हुये वीडियो के

शेष पृष्ठ 8 पर.....

यदि इनके त्यागपत्र पहले ही स्वीकार कर लिये जाते तो इस खर्च से बचा जा सकता था?

जब कांग्रेस के अपने ही विधायक सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहे थे तो निर्दलीय कैसे भरोसा करते

क्या सरकार और संगठन में तालमेल के अभाव के आरोप स्वयं पाटह्ल अध्यक्षा ने नही लगाये हैं?

क्या हाईकमान तक यह आरोप नहीं पहुंचे थे ?

उपचुनाव के लिये निर्दलीयों को ही जिम्मेदार मानना सही नहीं होगा।

क्या इन उपचुनावों के लिये सत्ता पक्ष ज्यादा जिम्मेदार नहीं है?

शिमला/शैल। प्रदेश में होने जा रहे तीन उपचुनावों में यह प्रश्न केन्द्रीय प्रश्न होता जा रहा है कि इन उपचुनावों के लिये जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अभी लोकसभा के साथ ही प्रदेश विधानसभा के लिये भी छः उपचुनाव हुये हैं । क्या यह उपचुनाव भी उन्हीं के साथ नहीं हो सकते थे? क्योंकि जिन निर्दलीय विधायकों के स्थानों पर यह उपचुनाव होने जा रहे हैं उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने के बाद अपने पदों से त्यागपत्र देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। यदि उनके त्यागपत्रों को तभी स्वीकार कर लिया जाता तो यह चुनाव भी साथ ही हो जाते। आज जो इन चुनावों के लिये करीब 30-40 करोड़ का खर्च होने जा रहा है उससे बचा जा सकता था। इसलिये इन उपचुनावों के लिये इन निर्दलीयों के साथ ही सत्ता पक्ष की राजनीति भी बराबर की जिम्मेदार है। इसी सवाल का दूसरा पक्ष है कि इन निर्दलीयों को अपने पदों से त्यागपत्र देने की नौबत क्यों आयी? यह निर्दलीय राज्यसभा चुनाव तक हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष के साथ खड़े रहे है। फिर उन्हें त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल होने की क्या आवश्यकता खड़ी हुई? इस सवाल का जवाब तलाशने

शेष पृष्ठ 8 पर.....

शारीरिक कसरत से कहीं ज्यादा एक गहन दर्शन है योग:शुक्ल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ऐतिहासिक गेयटी थियेटर शिमला में विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि योग को गहराई से जानना बेहद जरूरी है।

हमारी दिनचर्या के अभिन्न अंग बनने पर ही योग का पूर्ण लाभ लिया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि योग शारीरिक कसरत से कहीं ज्यादा एक गहन दर्शन है, जो मानव अस्तित्व की संपूर्णता को समाहित करता है।

संगोष्ठी का आयोजन देव भूमि सेवा संस्थान आश्रम शिमला द्वारा किया गया जिसका विषय था, ''योग एक सम्पूर्ण मानव दर्शन एवं योगचर्या।'' राज्यपाल ने कहा कि प्राचीन भारत में शुरू हुआ योग एक समग्र अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा को एकाग्र करता है। इसका उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण संतुलन और आंतरिक शांति की स्थिति को प्राप्त करना है। योग की बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक पूर्णता शामिल है।

उन्होंने कहा कि आज के भाग-दौड़ भरे जीवन में जहां अवसाद और चिंता इंसान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ऐसे में योग शांति और आत्ममंथन के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। ध्यानक्रिया से आंतरिक शांति, एकाग्रता, नकारात्मक विचारों का त्याग और समभाव की भावना का संचार होता है।

राज्यपाल ने कहा पूरा विश्व हमारे देश की इस योग परम्परा को अपना रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्थक प्रयासों से 21 जून, 2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में बेहद उत्साह के साथ मनाया गया और अब हर वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि योग की प्रासंगिकता व्यक्तिगत अभ्यास से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा दर्शन है जो करूणा, सचेतन और आत्मचेतना का संचार करता है। योग हमें आपस में तालमेल बिठाकर जीवन जीने और आसपास की दुनिया में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।

कार्यक्रम के अध्यक्ष वी. के. भटनागर ने राज्यपाल का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीनिवास मूर्ति ने योग की उपयोगिता पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

इससे पूर्व, देव भूमि सेवा संस्थान आश्रम के अध्यक्ष लेख राज राणा ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने अन्य प्रकल्पों के अतिरिक्त योग के जनजागरण का कार्य कर रहा है। संस्थान की प्रदेश भर में 70 संस्कार शालाएं कार्यरत हैं।

इस अवसर पर शिमला, तारादेवी के शगीन गांव के 10 वर्षीय सक्षम ठाकुर ने योगाभ्यास का प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया। राज्यपाल ने सक्षम की योग साधना की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया।

साई एटरनल फाउंडेशन के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

राज्यपाल मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संत कबीर जयंती की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को संत कबीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि संत कबीर की शिक्षाएं आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि संत कबीर की जीवन शैली और समाज के हर वर्ग के प्रति दयालुता का भाव आज भी हमारे लिए पथ-प्रदर्शक हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संत कबीर की कविताओं, दर्शनशास्त्र से भाईचारे और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से संत कबीर की शिक्षाओं का अनुसरण कर समाज को बेहतर बनाने का आहवान किया।

जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में सूखे की स्थिति के मद्देनज़र लोगों को पेयजल के साथ-साथ अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक स्त्रोतों में पेयजल की कमी, पेयजल आपूर्ति, पेयजल वितरण व पेयजल योजनाओं को हुए नुकसान की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

इस गंभीर स्थिति से निपटने और लोगों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हालात सामान्य होने तक जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

विभाग द्वारा सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी छुटी पर है तो वह तुरंत अपने तैनाती कार्यालय में रिपोर्ट करें।

उन्होंने कहा कि विभाग के प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को पेयजल आपूर्ति की कमी से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य की जनता को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम रिज पर आयोजित

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिज पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में योग क्रियाएं की। आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी योग में भाग लिया।

इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व योगमय हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और सम्पूर्ण विश्व इसे अपना रहा है। योग हमें प्राचीन संस्कृति, परम्परा और अध्यात्म से जोड़ता है। यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। वर्तमान में अधिकांश बीमारियां मानसिक स्वास्थ्य से संबन्धित होती है और मन को दृढ़ करने के लिए व्यक्ति को जीवन में योगाभ्यास अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि योग जीवन जीने की पद्धति है और लोगों को योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। यह हमारे जीवन की नकारात्मकता को दूर करने में भी मदद करता है। योग हमें प्रकृति के भी करीब लाता है, जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं।

इस अवसर पर विधायक जे.आर. कटवाल, वरिष्ठ अधिकारी, स्कूल के विद्यार्थी और गणमान्य लोगों ने यौगिक क्रियाएं की। इससे पहले, राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश के योगाध्ययन विभाग के डॉ. सत्य प्रकाश पाठक द्वारा राजभवन में आयोजित किए गए योग और ध्यान कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा और स्टाफ के अन्य सदस्यों ने भी योगासन किए।

उपचुनाव के मद्देनजर 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश घोषित किया

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान के मद्देनजर इन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 10 जुलाई, 2024 को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन इन क्षेत्रों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

उन्होंने बताया कि पंजाब के जालंधर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते ऊना, कांगड़ा, चंबा और सोलन जिलों में सेवाएं दे रहे पंजाब के पंजीकृत मतदाताओं और उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के चलते सिरमौर और शिमला में सेवाएं दे रहे उत्तराखंड के पंजीकृत मतदाताओं के लिए भी 10 जुलाई को विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

इन राज्यों में पंजीकृत मतदाता जो सरकारी, अर्ध-सरकारी और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

इसके अलावा इन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता जो अन्य स्थानों में काम कर कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है।

प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक सत्यापन की दिशा में करें कार्य

शिमला/शैल। भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य और आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद ने प्राकृतिक खेती के परिणामों की सराहना की और वैज्ञानिकों से इस पद्धति पर वैज्ञानिक डेटा का

आकलन करने का आग्रह किया। प्रोफेसर चंद हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान वह प्राकृतिक खेती से जुड़े वैज्ञानिकों और किसानों से बातचीत करेंगे।

प्रोफेसर चंद ने नौणी में डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय की प्राकृतिक खेती टीम के साथ एक बैठक की। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने उनका स्वागत किया और राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की गतिविधियों के बारे में बताया। प्रोफेसर चंद ने प्राकृतिक खेती को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए लगातार वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक उपज के प्रमाणीकरण और विपणन पर भी चर्चा की।

प्रोफेसर चंद ने सोलन के पास जौणाजी के प्रगतिशील किसान शैलेन्द्र शर्मा और शिल्ली के मनदीप वर्मा के खेतों का दौरा किया। दोनों किसान कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। शैलेन्द्र शर्मा ने विदेशी सब्जियों और सेब पर प्राकृतिक खेती के प्रभाव का प्रदर्शन किया, जबकि मंदीप वर्मा ने कीवी, उच्च घनत्व सेब की खेती और शीतोष्ण फलों के नर्सरी उत्पादन पर इसके प्रभावों पर चर्चा की। दोनों किसानों ने अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए और प्राकृतिक खेती के पर्यावरण और स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर चंद ने इस कृषि पद्धति को अपनाने और उसे बेहतर बनाने में और उनके नेतृत्व की सराहना की।

प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ एक संवाद सत्र मंगलवार को मशोबरा में विश्वविद्यालय क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। प्रोफेसर चंद स्टेशन पर विकसित सेब के प्राकृतिक खेती मॉडल का भी दौरा करेंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

स्क्रूटनी के बाद 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि स्क्रूटनी के उपरान्त अब तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनावों में अब कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 25 व 26 जून, 2024 को तीन बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं।

प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरा में अब कुल पांच, हमीरपुर में चार व नालागढ़ में छः प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में कमलेश (53) इण्डियन नेशनल कांग्रेस, होशियार सिंह (57), भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी सुलेखा देवी (590, अरूण अंकेश स्याल (34) तथा एडवोकेट संजय शर्मा (56) चुनावी मैदान में हैं।

विधानसभा क्षेत्र देहरा से दो कवरिंग प्रत्याशियों कांग्रेस के हरि ओम (66) तथा भाजपा के वीर सिंह (60) के नामांकन पत्र रद्द हुए। अब यहां से पांच प्रत्याशी है।

हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा (37) भारतीय जनता पार्टी भाजपा, डॉ. पुष्पिंदर वर्मा (48) इण्डियन नेशनल कांग्रेस तथा निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार (58) व नन्द लाल शर्मा (64) चुनावी मैदान में हैं।

विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर से कोई भी नामांकन रद्द नहीं हुआ। यहां से चार प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से हरदीप सिंह बावा (44) इण्डियन नेशनल कांग्रेस, के.एल. ठाकुर (64) भारतीय जनता पार्टी भाजपा, किशोरी लाल शर्मा (46) स्वाभिमान पार्टी तथा गुरनाम सिंह (48), हरप्रीत सिंह (36) व विजय सिंह (36) निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नालागढ़ क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी उदय कुमार सिंह (46) तथा कांग्रेस के कवरिंग प्रत्याशी परमिंदर कौर बावा (430) का नामांकन रद्द हुआ। यहां से अब छः प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से हिमाचल को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश का आग्रह किया

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से जुड़ी हिमाचल प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं तथा अन्य मुद्दों पर 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी। यह प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के तीन दिवसीय प्रवास पर है, जो आगामी पांच वर्षों के लिए हिमाचल के संबंध में अपनी सिफारिश देगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त आयोग के समक्ष राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाया तथा राष्ट्र निर्माण में प्रदेश के योगदान को देखते हुए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया, ताकि इन क्षेत्रों से स्थानीय लोगों का पलायन रोका जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, जिसके चलते हिमाचल को आपदा पूर्व प्रबन्धन एवं राहत कार्यों की दृष्टि से विशेष प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। हिमाचल सहित अन्य हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में आपदाओं की अधिक संभावनाएं होने के कारण इन क्षेत्रों के लिए आपदा जोखिम सूचकांक तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने आयोग को बताया कि पिछले वर्ष बरसात में भारी बारिश एवं बाढ़ से हुए नुकसान के एवज में केंद्र सरकार ने 9,042 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके कारण राज्य को हजारों करोड़ का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है और प्रदेश को अब तक इस नुकसान के लिए भी मुआवजा नहीं मिला है। राष्ट्र हित को देखते हुए हिमाचल ने पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है, जिसके कारण हिमाचल को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य को वन मंजूरी अधिनियम के तहत वर्ष 2017 से कोई अनुमति नहीं मिली है।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमाचल प्रदेश का राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल प्रदेश ने भाखड़ा बांध और पौंग बांध के लिए लाखों एकड़ जमीन दी है तथा हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान प्रदेश को सिंचाई के लिए पानी प्रदान करता रहा है। इसी तरह, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य को कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है और प्रदेश सरकार को शानन पन विद्युत परियोजना की पट्टा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी मालिकाना हक नहीं मिला है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनावश्यक संस्थानों को बंद करने जैसे बड़े कदम उठाए हैं। इसके अलावा, प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृषि, पशुपालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को अधिमान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने 16वें वित्तायोग से राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास के लिए उदारवादी वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश करने का आग्रह किया।

इससे पूर्व, 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डॉ. अरविन्द पनगढ़िया ने अपने संवाद में राज्य की उपलब्धियों विशेषकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए।

प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने वित्त आयोग के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी।

आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. निरंजन राजाध्यक्षा, डॉ. सौम्या कांति घोष, सचिव रित्विक पांडा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव एवं शिक्षा सचिव राकेश कंवर सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने वीरभद्र सिंह की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में श्रद्धासुमन अर्पित किये। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपना पूरा जीवन विकास और राज्य की जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। प्रदेश को खुशहाल और आधुनिक राज्य बनाने के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किये।

मुख्यमंत्री ने ऊना में 356.72 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के ऊना और हरोली विधानसभा क्षेत्रों के लिए 356.72 करोड़ रुपये की सात विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने पेखूबेला में 220 करोड़ रुपये की 32 मेगावाट डीसी क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना, 92 लाख रुपये के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन पीरनिगाह (बसोली) और ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए 42 लाख रुपये की स्वास्थ्य उप-केंद्र जंकार का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने पन्जुआना में प्रशासनिक और टाउनशिप ब्लॉक से कुठेड़ बीट में बल्क ड्रग पार्क के फैक्ट्री गेट तक 42.04 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले संपर्क मार्ग, 73.84 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले प्रशासनिक और आवासीय ब्लॉक बल्क ड्रग पार्क परियोजना, 14.44 करोड़ रुपये की लागत से पोलियां गांव में बल्क ड्रग पार्क स्थल के लिए 10 एमवीए बिजली आपूर्ति और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के 132/33 केवी सब-स्टेशन के समीप टाहलीवाल में 15.83 करोड़ रुपये की लागत से 220/132 केवी 100 एमवीए सब स्टेशन (50 एमवीए की अधिकतम सीमा के साथ) के साथ स्थापित किया जाएगा।

कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे।

मंत्रिमण्डल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमण्डल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। लोगों को घर-द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में प्रोफेसर के तीन तथा एसोशिएट प्रोफेसर के दो पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नैरचौक, मंडी में प्रोफेसर के दो तथा एसोशिएट प्रोफेसर का एक पद, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के चार तथा एसोशिएट एवं सहायक प्रोफेसर के पांच-पांच पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपाकालीन चिकित्सा अधिकारी के आठ पद सृजित कर भरने तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पांच पद सृजित कर भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थियेटर सहायक, तकनीशियन, मल्टी टास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में राज्य में नवगठित फोर लेन नियोजन क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में युवा आयोजकों के चार पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डो, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। बैठक में जिला ऊना के हरोली में विद्युत बोर्ड का मण्डलीय कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने और होम-स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति भी गठित करने का निर्णय लिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति को स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस उप-समिति के सदस्य होंगे।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में वनों की आग, सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की।

प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को दे रही अधिमान:राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को स्वावलम्बी बनने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में 364 तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उनका कौशल संवर्धन किया जा रहा है। इन संस्थानों में सुचारू रूप से बच्चों को प्रशिक्षण मिले, इसलिए तकनीकी शिक्षा विभाग में युक्तिकरण प्रक्रिया को शुरू किया गया है। विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लगभग 80 कर्मचारियों का युक्तिकरण किया गया है। इस कदम से व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही तकनीकी संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के दृष्टिगत आधुनिक शैक्षणिक पाठयक्रम आरम्भ किए गए हैं। युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और बहुतकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग जैसे नवीन पाठयक्रम शामिल किए गये हैं। विभाग द्वारा युवाओं के लिए बेहतर प्लेसमेंट के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं।

कनिष्ठ कार्यालय सहायक के लिए दस्तावेजों का मूल्यांकन

शिमला/शैल। राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग में दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कनिष्ठ कार्यालय सहायक जेओए के दो पदों को भरने के लिए 24 जून को दोपहर 12 बजे दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है वे सभी अभ्यर्थी शिमला में कसुम्पटी स्थित ब्लॉक नंबर-33 एसडीए कम्पलैक्स, निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण कार्यालय में रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय और स्थान पर रिपोर्ट करें। अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेज दिए गए हैं। कॉल लेटर राज्य कर एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट www.hptax.gov.in से भी डाऊनलोड किए जा सकते हैं।

किसी चीज से डरो मत। तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष होना

इस बार संसद में एक सशक्त विपक्ष देखने को मिलेगा यह स्पष्ट हो गया है। विपक्ष की संख्या देखकर यह भी लगने लगा है कि आने वाले दिनों में यदि सरकार सही से अपने कार्यो का निष्पादन नहीं कर पायी तो उसे हराया भी जा सकता है। स्थिर सरकार और सशक्त विपक्ष दोनों एक साथ होना लोकतंत्र की पहली और बड़ी आवश्यकता है। इस बार विपक्ष को इस संख्या बल तक पहुंचने का सबसे बड़ा श्रेय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जाता है। यह उनकी दोनों यात्राओं का प्रतिफल है कि एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष के पद की पात्र हो गयी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद के लिये नामजद करके एक सही फैसला लिया है। नेता प्रतिपक्ष के नाते वह एक तरह से प्रधानमंत्री के समकक्ष हो जाते हैं। क्योंकि अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच आधिकारिक वार्तालाप होता रहेगा। दोनों नेताओं को एक दूसरे को वैचारिक स्तर पर समझने का मौका मिलेगा। पिछले दस वर्षो में कोई सशक्त विपक्ष न होने के कारण प्रधानमंत्री और सरकार दोनों एक तरह से निरंकुश हो गये थे। क्योंकि मोदी भाजपा संगठन से ऊपर हो गये थे और इसका प्रमाण तब सामने आया जब चुनावों के दौरान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरएसएस को उसकी सीमाओं का स्मरण कराया। आज राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन में एक सार्वजनिक पद पर आसीन हो गये हैं। अब उनकी सोच और कार्यशैली की आधिकारिक समीक्षा होगी और सार्वजनिक रूप से सबके सामने रहेगी।

एक समय देश कोबरा स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से यह देख चुका है कि उनको पप्पू प्रचारित करने के लिए कैसे और किस स्तर तक निवेश किया गया था। पिछले दस वर्षो में विपक्ष और देश ने जो कुछ जिया भोगा है उस सबके गुणात्मक आकलन का अवसर अब आया है। इस दौरान कैसे प्रभावशाली लोगों का लाखों करोड़ का ऋण माफ हो गया? कैसे सार्वजनिक संस्थान एक के बाद एक निजी क्षेत्र के हवाले होते चले गये? दस वर्षो में दो बार नोटबंदी की नौबत क्यों आयी? क्यों सरकार में सरकारी रोजगार के अवसर कम होते चले गये? ईडी के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष को क्यों सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा? जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सर्वसुलभ और नि:शुल्क होने चाहिये वहीं पर यह आम आदमी की पहुंच से बाहर क्यों होते जा रहे हैं। पेपर लीक हर परीक्षा में हर राज्य में क्यों होने लग गया है? जितने सवाल देश के सामने आज तक उठाये गये हैं अब उनके सही जवाब देश के सामने लाना एक बड़ी जिम्मेदारी और आवश्यकता होगी। पिछली बार किस आंकड़े तक विपक्ष के सांसदों का निलंबन हो गया था यह देश ने देखा है। तीन अपराधिक कानूनों का मानसून सत्र के अंतिम दिन कैसे बिना बहस के पारण हो गया यह देश देख चुका है। अब यह संशोधित कानून पहली जुलाई से लागू होने जा रहे हैं।

अब इन कानूनों पर संसद में खुली बहस किये जाने की मांग टीएमसी नेता ममता बनर्जी की ओर से आ गयी है। यह कानून पूरे देश और उसके भविष्य को प्रभावित करेंगे। देश के सौ से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने महामहिम राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखकर इन कानूनों पर अमल रोकने और इन पर संसद में बहस की मांग उठाई है। क्योंकि पिछली बार सौ से अधिक सांसद निलंबित थे। इसलिए इन पर एक विस्तृत बहस देश हित में आवश्यक है। नई संसद के पहले सत्र में ही देश के सामने आ जायेगा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में किस तरह का तालमेल होने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री किस तरह से इस अहम मुद्दे का हल निकालते हैं। इसी से यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार और विपक्ष में आने वाले समय में रिश्ते कैसे रहते हैं। राहुल गांधी को यह प्रमाणित करने का अवसर होगा कि वह विकल्प है। इसी तरह प्रधानमंत्री के लिये भी यह सबका विकास और सबका साथ का टेस्ट होगा। गठबंधन के नेता के तौर पर यह मोदी का भी टेस्ट होगा।

हमारे बारह' पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, फिल्मी के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं आएं आगे

गौतम चौधरी

लंबे अरसे से विवादों में रही 'हमारे बारह' फिल्म को आखिरकार सिनेमाघरों तक पहुंचने की हरी झंडी मिल गई। हालांकि इस फिल्म के तीन महत्वपूर्ण संवाद बदल दिया गया है लेकिन अब यह फिल्म दर्शकों के लिए तैयार हैं। फिल्म बनाने वालों का दावा है कि इसे महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देखा जाना चाहिए लेकिन मजहब के पाबंदों का आरोप है, यह फिल्म इस्लामिक मान्यताओं को लक्ष्य कर बनाया गया है। जो भी हो लेकिन अब फिल्म सिनेमाघरों में है।

फिल्म की कहानी एक प्रगतिशील मुस्लिम युवा लड़की द्वारा न्यायालय के दरवाजे से प्रारंभ होती है। फिल्म में देश के कानून और इस्लामिक मान्यताओं में साफ तौर पर गतिरोध दिखाया गया है। एक परंपरिक मुस्लिम परिवार में 11 बच्चे पहले से होते हैं। घर का मुखिया जो 60 की उम्र का है, वह अपनी आधी उम्र की दूसरी पत्नी से 12वां बच्चा चाहता है। पत्नी गर्भवती तो है लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति बच्चा जनने लायक नहीं है। चिकित्सकों की राय है कि वह अबॉर्शन करवा ले लेकिन उसका पति इसके लिए तैयार नहीं है। वह वहां धर्म की दुहाई देता है। फिल्म की पटकथा कुछ इसी तरह है। इस बीच घर के मुखिया की बेटी आगे आती है और अपनी सौतेली मां को लेकर कोर्ट चली जाती है। फिल्म इसी के चारों ओर घूमता रहता है।

इस फिल्म ने मुस्लिम समुदाय और विद्वानों के बीच चिंता पैदा कर दी है। फिल्म को लेकर मुस्लिम समुदाय नाराज दिख रहा है। मामले को लेकर कई स्थानों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। उनका आरोप है कि इस फिल्म में इस्लामी शिक्षाओं को नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है। फिल्म के आलोचकों का तर्क है कि इसमें कुरान और हदीस की शिक्षाओं को नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही मुसलमानों को प्रगतिशीलता के खिलाफ बताया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।

फिल्म में उठाए गए मुद्दों, जैसे मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न, जनसंख्या विस्फोट, पितृसत्ता आदि को बेहतर तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में यह भी बताया गया है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की शिक्षा को तवज्जो नहीं दिया जाता है। इसे समस्या के रूप में चिन्हित किया गया है। सच पूछिए तो भारतीय मुस्लिम समाज में इस प्रकार की समस्या तो है लेकिन मूल इस्लाम का वास्तविक रूप ऐसा नहीं है। मूल इस्लाम में महिलाओं को शिक्षित होना अनिवार्य बताया गया है। सामान्य-सी बात है, कोई सभ्यता या समूह तभी मजबूत होता है, जब वहां की महिलाएं सशक्त होती है। महिलाएं तभी सशक्त होगी जब उसे शिक्षित किया जाए। इस्लाम में भी ऐसा ही है। यदि महिलाओं को शिक्षित बनाया जाए तो वही महिला आगे चलकर इस्लाम की ताकत बन जाएगी। इस फिल्म पर हंगामा करने के बजाय, मुस्लिम समुदाय की विद्वान महिलाओं को आगे आना चाहिए और अपने ज्ञान व तर्क-बुद्धि से ऐसे आख्यानों का खंडन करना चाहिए, जो उनके धर्म के खिलाफ है। प्रभावशाली या शक्तिशाली पद पर आसीन एक मुस्लिम महिला यदि ऐसा करती है, तो उसका प्रभाव दूर तक पड़ेगा।

इस्लाम हिंसा से घृणा करता है। यह अपने अनुयायियों से देश के कानून का पालन करने के लिए भी कहता है। इस मामले में लाभ कमाने वाले प्रोडक्शन हाउसों की रणनीति में फंसने के बजाय, मुसलमानों को राजनीतिक कौशल का परिचय देना चाहिए। फिल्म के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। कोई भी हिंसक दृष्टिकोण केवल ऐसी कहानियों को बढ़ावा देगा और समुदाय को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करेगा।

इस्लाम, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा को उच्च महत्व देता है। इस्लाम के अंतिम नवी ने साफ तौर पर कहा है कि ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान का दायित्व है। 'हमारे बारह' जैसी फिल्मों द्वारा सामने लाए गए मुद्दों के प्रकाश में, मुसलमानों के लिए खुद को और दूसरों को इस्लाम के सच्चे सिद्धांतों के बारे में बताना चाहिए। इस पर एक मीडिया कैंपेन भी चलाया जा सकता है। गलत सूचना और पूर्वाग्रह से निपटने के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने विश्वास के मूल मूल्यों को समझकर और उनका अभ्यास करके, मुसलमान इस्लाम के सच्चे सार को प्रदर्शित कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय को रचनात्मक बातचीत में शामिल होना चाहिए और मीडिया में गलत बयानी का तर्क के साथ खंडन करना चाहिए। इस लड़ाई के बीच देश के लोकतांत्रिक ढांचे व कानून का सम्मान भी जरूरी है।

मामला चाहे जो भी हो, हिंसा का सहारा लेने के बजाय शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से ऐसे आख्यानों का मुकाबला करना और इस्लामी शिक्षाओं की सटीक समझ को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना आधुनिकता का मापदंड बन गया है। ऐसे में सड़कों पर उतरने से ज्यादा बढ़िया न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। इसके अलावा, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करके और उनकी उपलब्धियों को समुदाय के सामने बोलने की अनुमति देकर, मुसलमान अपने विश्वास के सच्चे सिद्धांतों का प्रदर्शन कर सकते हैं।

विश्व जल सर्वेक्षण दिवस 2024

शिमला। प्रत्येक वर्ष 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन (आईएचओ) जल विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुद्रों और महासागरों के बेहतर ज्ञान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए विश्व जल विज्ञान दिवस मनाता है। वर्ष 2024 के विश्व जल विज्ञान दिवस का विषय 'जल विज्ञान सूचना - समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना' है, जो नौवहन में चल रहे परिवर्तन, जैसे कि ई-नौपरिवहन, स्वायत्त जल यात्रा और कार्बन उत्सर्जन में कमी के कारण जल विज्ञान सेवाओं के गहन विकास को ध्यान में रखते हुए रखा गया है।

भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग (आईएनएचडी) भारत में जल विज्ञान सर्वेक्षण और समुद्री चार्टिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय नौसेना के अंतर्गत कार्य करता है। विभाग के पास जल विज्ञान सर्वेक्षण करने और नौपरिवहन चार्ट प्रकाशित करने का शासनादेश है। आज तक, दुनिया भर के व्यापारी नाविकों और नौसेनाओं के उपयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र को कवर करने वाले 650 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक और पेपर नौपरिवहन चार्ट प्रकाशित किए गए हैं। पिछले वर्ष, विभाग ने इन जल क्षेत्रों में काम करने वाले नाविकों को 6.5 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक नौपरिवहन चार्ट वितरित किए हैं और राजकोष को लगभग 8000 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसके भविष्य में और बढ़ने का अनुमान है।

एनएचीएआरईए VIII समन्वयक के रूप में विभाग, भारतीय महासागर के 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और वेब पोर्टल 'इंडिया विन्स-भारतीय चेतावनी सूचना और नेविगेशन सेवाएँ' के माध्यम से समुद्र में नौपरिवहन की सुरक्षा से संबंधित जानकारी साझा करता है। यह मॉडयूल लगभग वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है और दिसंबर 2022 में इसके शुरू होने के बाद से, यह सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को ध्यान में रखते हुए प्रति दिन औसतन 3500 से अधिक आगंतुकों के साथ 3.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया है।

गोवा में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) जल विज्ञान में प्रशिक्षण देने का केंद्र है और इसे कैट ए और कैट बी प्रमाणपत्रों के पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है। आज तक, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संस्थान (एनआईएच) में 41 विभिन्न देशों के 800 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

भारत सरकार की सागर पहल के अनुरूप, भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण जहाजों ने पिछले पांच वर्षो में 89000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए मित्र देशों के साथ विभिन्न संयुक्त सर्वेक्षण अभियान चलाए हैं और 96 चार्ट तैयार किए हैं। विभाग ने क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के माध्यम से भी उनकी सहायता की है। ये प्रयास स्वदेशी रूप से निर्मित सर्वेक्षण जहाजों द्वारा विशाल हिंद महासागर क्षेत्र का मानचित्रण करके किये जाते हैं।

विश्व जल विज्ञान दिवस के एक हिस्से के रूप में, 20 जून 24 को राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में - जल विज्ञान सूचना-समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता बढ़ाने पर एक समुद्री कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में 25 से अधिक भारतीय बंदरगाहों और कार्यालयों के मेहमानों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया था। इसके अलावा, यह कार्यालय पिछले वर्ष तक नई दिल्ली में संयुक्त सचिव बंदरगाहों के कार्यालय के परामर्श से जल विज्ञान सर्वेक्षण समिति की बैठकें आयोजित करता रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हीटवेव संबंधी एडवाइजरी जारी की

शिमला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नडडा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश भर में लू की स्थिति और लू से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की।

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अस्पताल हीटवेव से प्रभावित लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए तैयार रहें।

नडडा ने केंद्र सरकार के अस्पतालों में विशेष हीटवेव यूनिट्स शुरू करने का भी निर्देश दिया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है।

हीट वेव सीज़न 2024 पर राज्य स्वास्थ्य विभाग के लिए एडवाइजरी:

गर्मियों के तापमान के देखे गए ट्रेंड के अनुरूप देश में मौसमी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो सकता है। अत्यधिक गर्मी से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए, स्वास्थ्य विभागों को तैयारी और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करनी होगी।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम एनपीसी सीएचएच के तहत राज्य नोडल अधिकारियों को निम्नलिखित गतिविधियां सुनिश्चित करनी होंगी:

1. **सभी जिलों में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का प्रसार:**

गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

भारत में गर्मी से संबंधित बीमारियों एचआरआई के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी को मजबूत करना।

हीटवेव की रोकथाम और प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के दिशानिर्देश।

2. **हीट-हेल्थ एक्शन प्लान,** राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राज्य कार्य योजना का एक चौप्टर, को लागू करें।

केंद्रित तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए जिला-विशिष्ट व शहर-स्तरीय ताप-स्वास्थ्य कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करें।

3. जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राज्य एवं जिला टास्क फोर्स के साथ बैठक।

राज्य/जिला स्तर पर हीट हेल्थ एक्शन प्लान को अपडेट करने और अनुमोदन के लिए एक टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करें। इस योजना में **'मानक संचालन प्रक्रियाओं'** एसओपी का विवरण होना चाहिए जो हीटवेव के मौसम के दौरान लागू होंगी।

तैयार किए गए हेल्थ सेक्टर हीट एक्शन प्लान को जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के लिए राज्य कार्य योजना एसएपीसीसीएचएच में शामिल किया जाएगा और इसकी एक कॉपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए या राहत आयुक्त विभाग को हीटवेव पर राज्य कार्य योजना में शामिल करने के लिए भेजी जा सकती है।

4. गर्मी से संबंधित बीमारी और मृत्यु निगरानी के तहत रिपोर्टिंग

जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आईएचआईपी पोर्टल पर 1 मार्च, 2024 से हीटस्ट्रोक के मामलों और मौतों, आपातकालीन उपस्थिति और कुल मौतों पर दैनिक डेटा जमा करना शुरू करें।

पी-फॉर्म स्तर पर एंट्री का उपयोग करके निर्दिष्ट फॉर्म कुल/रोगी-स्तर के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं, पीएचसी और उससे ऊपर का डेटा जमा करें

स्वास्थ्य सुविधा/अस्पताल स्तर पर हीटस्ट्रोक के मामलों और मौतों संदिग्ध/पुष्टि की डिजिटल लाइन सूची का दिए गए प्रारूप में रखरखाव सुनिश्चित करें।

गर्मी से संबंधित बीमारी से होने वाली प्रत्येक संदिग्ध मृत्यु (संलग्न) हेतु चिकित्सा अधिकारी/महामारी विशेषज्ञ संदिग्ध गर्मी से संबंधित बीमारी से मौत की जांच करें गर्मी से संबंधित बीमारी पर राष्ट्रीय कार्य योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विवरण ताकि संदिग्ध एचआरआई मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों को समझा जा सके।

5. भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी द्वारा प्रतिदिन 1600 बजे भारतीय समय के बाद जारी की जाने वाली हीटवेव्स की **पूर्व-चेतावनी का प्रसार,** जिसमें अगले चार दिनों का पूर्वानुमान शामिल है, को स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादा प्रभावित आबादी तक किया जाना चाहिए।

6. जनता को अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करने के लिए समय-समय पर **स्वास्थ्य सलाह जारी करें और आईईसी गतिविधियों की योजना बनाएं।** एनसीडीसी द्वारा सामान्य और ज्यादा प्रभावित आबादी के लिए हीटवेव पर तैयार की गई आईईसी सामग्री (https://ncdc. mohfw .gov.in/index1. php?lang=1&level= 3&sublinkid =1091&lid=556) पर उपलब्ध है। जरूरत पड़ने पर क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद के बाद राज्य में आईईसी तैयार करने के लिए इसे टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

7. एचआरआई लक्षणों, मामले की पहचान, नैदानिक प्रबंधन, आपातकालीन कूलिंग और निगरानी रिपोर्टिंग पर स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की **संवेदनशीलता और क्षमता निर्माण।**

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जन जागरूकता उपायों, व्यक्तिगत कूलिंग उपायों, एचआरआई पहचान, प्राथमिक चिकित्सा, रेफरल और रिपोर्टिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नोडल अधिकारी, चिकित्सा अधिकारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और समुदाय के लिए एनपीसीएचएच द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण मैनुअल (https://ncdc.mohfw. gov.in/index1.php?lang= 1&level= 2&sublinkid =922&lid =697) का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया जाना चाहिए।

8. गंभीर एचआरआई की रोकथाम और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सुविधा की तैयारी मात्रा में कमी और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन आदि के प्रबंधन में सहायता के लिए पर्याप्त मात्रा में ओआरएस पैक, आवश्यक दवाएं, आईवी तरल पदार्थ, आइस-पैक और उपकरणों की खरीद और आपूर्ति।

एक्टिव कूलिंग स्ट्रेटेजी की पहचान करें जिनका उपयोग उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्वास्थ्य केंद्रों और क्षेत्र स्तरों पर किया जा सकता है, आंतरिक प्रोटोकॉल विकसित करें, स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें।

भीषण गर्मी से संबंधित बीमारी के रोगियों की आपात स्थिति, तेजी से कूलिंग सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों और एम्बुलेंस के लिए संसाधनों की पहचान/खरीद करें। (एनपीसीसी एचएच पीआईपी वित्तीय वर्ष 24-25, 25-26 दिशानिर्देश)

सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

प्रतीक्षा और रोगी उपचार क्षेत्र में सामान्य कूलिंग उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता और उनकी फंक्शनिंग सुनिश्चित करें।

संदिग्ध हीट स्ट्रोक वाले मामलों का तेजी से आकलन किया जाना चाहिए और मानक उपचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके सक्रिय रूप से बेहतर उपचार किया जाना चाहिए।

9. अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती

कूलिंग एप्लायंस के निरंतर कामकाज के लिए अस्पतालों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली वितरण कंपनी/निगम के साथ समन्वय करें।

स्वास्थ्य केंद्रों में इनडोर गर्मी और ऊर्जा संरक्षण को कम करने के लिए ठंडी छत/ग्रीन छत, खिड़की की छाया, वर्षा जल संचयन, सोलराइजेशन आदि उपाय अपनाएं।

ज्यादा गर्म जगहों वाले स्वास्थ्य केंद्रों के बाहर शेड की व्यवस्था करें

10. एचआरआई-केंद्रित सामूहिक सभा/खेल आयोजन की तैयारी

गर्मियों के दौरान सामूहिक सभा या खेल गतिविधियों का आयोजन करते समय, स्वास्थ्य विभागों, अन्य संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से गर्मी से संबंधित बीमारियों एचआरआई को रोकने और प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त तैयारी की जानी चाहिए।

इवेंट प्लानिंग के लिए इन बातों पर ध्यान दें-

पर्यावरणीय ताप।

लू के पूर्वानुमान, उच्च आर्द्रता, सक्रिय लू की चेतावनियों को देखें और स्थानीय आईएमडी केंद्र से परामर्श लें।

उन दिनों से बचें जब सक्रिय लू की चेतावनी, उच्च आर्द्रता की संभावना हो।

दिन के सबसे गर्म समय (दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक) में बाहरी कार्यक्रमों की योजना बनाने से बचें।

इवेंट ग्राउंड पर सुविधाएं/बुनियादी व्यवस्थाएं।

चिकित्सा शिविर, कूलिंग एरिया, पानी की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं की एक चिकित्सा टीम के साथ कार्यक्रम स्थल/मैदान के मूल्यांकन की योजना बनाएं।

सुरक्षित, पेयजल प्रावधान।

सभी उपस्थित लोगों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित जल आपूर्ति व सुविधाजनक पहुंच की व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रति व्यक्ति आवश्यक पानी की सुझाई गई मात्रा 20 लीटर/दिन और पीने के लिए 4 लीटर है।

पूरे दिन के आयोजनों के लिए जल प्रावधान की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जा सकती है-

1. प्रति व्यक्ति कम से कम 2 लीटर निःशुल्क पेयजल उपलब्ध हो या 500 मि.ली./घंटा की दर से गणना की गई हो, जो भी अधिक हो और

2. प्रति 500 लोगों पर एक जल आउटलेट की व्यवस्था हो।

3. सुरक्षा, पानी की गुणवत्ता व स्वच्छता के लिए जल आउटलेट की समीक्षा और अनुमोदन किया जाना चाहिए।

आपातकालीन कूलिंग/छिड़काव के लिए पानी की मात्रा पर अलग से विचार किया जाना चाहिए।

शेड/शेल्टर: उपस्थित लोगों के खुले में सूर्य के संपर्क में आने को कम करने के लिए।

कूलिंग शेल्टर्स: कुएं, सक्रिय रूप से हवादार/ठंडे कमरे/धुंध वाले क्षेत्रें का प्रावधान।

हेल्थ प्रमोशन और जोखिम संबंधी संचार

भाग लेने वाली आबादी के लिए स्थानीय भाषा में लगातार संचार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें, ङ्ककार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम के दौरानङ्ग सोशल मीडिया, साइट पर पोस्टर, उपायों के बारे में वीडियो क्लिप/घोषणाओं के माध्यम से।

डिहाइड्रेशन से बचना/पर्याप्त पानी का सेवन।

उचित कपड़े पहनें और सनस्क्रीन, टोपी, छाता आदि जैसे सुरक्षात्मक उपाय करें।

गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा कम करें।

एचआरआई के प्राथमिक संकेतों-लक्षणों, प्राथमिक चिकित्सा और प्रथम उत्तरदाताओं से संपर्क करने के तरीकों की पहचान करना।

स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारी

स्वास्थ्य निगरानी, चिकित्सा प्रबंधन और प्रतिक्रिया योजना में गर्मी से संबंधित बीमारियों पर विचार करें।

घटना के प्रकार के आधार पर संभावित ज्यादा प्रभावित आबादी की सामान्य समझ रखें। सामूहिक खेल आयोजनों में अत्यधिक हीटस्ट्रोक देखा जा सकता है, तीर्थयात्रा से संबंधित सामूहिक सभा में क्लासिक हीटस्ट्रोक आम हो सकता है।

मात्रा में कमी और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन आदि के प्रबंधन में सहायता के लिए ओआरएस पैक, आवश्यक दवाएं, आईवी तरल पदार्थ, आइसपैक और उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से गर्मी से संबंधित बीमारी (एचआरआई) को रोकें।

गर्मी से संबंधित गंभीर बीमारियों के तुरंत आकलन और तुरंत रोकथाम को प्राथमिकता दें।

गर्मी की थकावट और हीटस्ट्रोक के रोगियों के पूरे शरीर को तेजी से ठंडा करने के लिए सुरक्षित, सुलभ क्षेत्र निर्दिष्ट करें।

पानी, शेड, वेन्यू की टॉपोग्राफी और पहुंच के आधार पर उपयुक्त त्वरित कूलिंग विधि की पहचान करें, इसी के मुताबिक उपकरण (रेक्टल थर्मामीटर, बर्फ के बक्से, बर्फ के टुकड़े, ठंडा पानी, टारप, आइस कूलर, पंखे, तौलिए/चादरें) खरीदें और कूलिंग एरिया तैयार करें।

परीक्षण, तुरंत मूल्यांकन, त्वरित कूलिंग, चिकित्सा रिकॉर्ड रखने, रेफरल और निगरानी में उपस्थित चिकित्सा कर्मचारियों और संबंधित प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने वाले स्टाफ का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।

निकटतम रेफरल स्वास्थ्य केंद्रों को नामित और सूचित करें जो पर्याप्त एचआरआई प्रबंधन और शीतलन सुविधाएं प्रदान कर सकें।

गंभीर रोगियों को निकटतम सभी सुविधाओं से लैस स्वास्थ्य देखभाल केंद्र तक पहुंचाने के लिए आइस पैक और ठंडे पानी आदि के साथ एम्बुलेंस तैयार रखें।

इवेंट के दौरान इन बातों पर ध्यान दें-

पर्याप्त एयर सर्कुलेश सुनिश्चित करें, कार्यक्रम स्थल पर भीड़भाड़ से बचें।

प्रवेश द्वार पर और कार्यक्रम क्षेत्र के भीतर चेकपॉइंट्स के साथ कार्यक्रम में ज्यादा प्रभावित लोगों की पहचान और निगरानी करें, साइट पर स्वयंसेवकों/कैमरों की मदद से निगरानी।

उपयुक्त पोर्टेबल आइस बॉक्स, ठंडे पानी, ओआरएस पैकेट के साथ वर्दीधारी चिकित्सा सहायता टीमों को तैनात किया जाना चाहिए।

गर्मी के प्रभावों और हाइड्रेटेड व ठंडे रहने के रीमाइंडर्स के संबंध में अच्छा सार्वजनिक संचार (प्रसारण, पोस्टर के संदर्भ में) जारी रखें।

कार्यक्रम स्थल के विस्तृत मानचित्र और प्रदर्शन पर दिशा-निर्देशों के माध्यम से जनता को मेडिकल चेक पोस्ट्स, निकटतम निकास की ओर मार्गदर्शन करें।

एचआरआई के लिए इलाज किए गए सभी रोगियों का उचित प्रबंधन एवं दस्तावेज़ीकरण और उनके फर्स्ट एड के बाद फॉलोअप सुनिश्चित करें।

एनपीसीसीएचएच के तहत गर्मी से संबंधित बीमारी और मृत्यु निगरानी में हीटस्ट्रोक के मामलों और मौतों की रिपोर्ट करें।

हेल्थकेयर टीम और इवेंट का आयोजन करने वालों के बीच प्रभावी संचार कायम करके रखें।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का अब तक 48 हजार से अधिक महिलाओं को मिल चुका है लाभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के हरोली स्थित कांगड़ मैदान में आयोजित समारोह में 7,280 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि के तहत 4500-4500 रुपए तीन महीने की सम्मान निधि के रूप में 3.27 करोड़ रुपए जारी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं को चेक भी वितरित किए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 18 से 59 वर्ष आयु की 48 हजार से अधिक महिलाओं को 4500-4500 रुपए तीन महीने की सम्मान-निधि के तौर पर जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 23 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा प्रदेश की महिलाओं को योजना के बारे में लगातार गुमराह कर इसे लागू करने में अड़ंगे लगाती रही।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर बार-बार पूछते थे कि महिलाओं को 1500 रुपए कब मिलेंगे लेकिन हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर महिलाओं को सम्मान निधि प्रदान की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्रदान कर रही है, जबकि प्रदेश कांग्रेस सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 18,000 प्रति वर्ष प्रदान कर रही है, ताकि वे स्वाभिमान के साथ जीवन-यापन कर अपने खर्चों के लिए अन्यों पर निर्भर न रहें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर महीने पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रदान करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कभी भी चुनाव को देखकर राजनीति नहीं करती, बल्कि जन-सेवा ही हमारा एकमात्र ध्येय है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था तथा भाजपा नेताओं ने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया था। लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब किया लेकिन अब वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। बीते दिन हुई कैबिनेट बैठक में हरोली में बिजली बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 2,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर करवाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हरोली विधानसभा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रूपये की लागत से ब्लक ड्रग पार्क स्थापित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने हिमकेप्स लॉ एवं नर्सिंग कॉलेज बढेड़ा में जीएनएम की सीटें 40 से बढ़ाकर 60 करने की घोषणा की। उन्होंने दुलैहड़ पार्क तथा बीटन मैदान के सुधार के लिए 50-50 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। उप-मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विकासात्मक घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना की शुरूआत हरोली विधानसभा क्षेत्र से करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रे ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की निधि रुकवाने के लिए भाजपा ने काफी हथकंडे अपनाए लेकिन वर्तमान सरकार ने इस साजिश को सफल नहीं होने दिया। भाजपा नेता महिलाओं के बीच जाकर लगातार पूछते थे कि 1500 रुपये कब मिलेंगे। यहीं नहीं, भाजपा ने सम्मान निधि योजना के फॉर्म भरने से भी महिलाओं को रोका और कहा कि यह सिर्फ समय की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं भाजपा नेताओं की बातों में आ गई लेकिन जिन महिलाओं ने फार्म भरे उन्हें आज 4500-4500 रुपये मिले हैं। यह प्रदेशवासियों का कांग्रेस सरकार के प्रति भरोसा और विश्वास है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनेता का वायदा सबसे बड़ा भरोसा होता है। वे 25 साल से इस क्षेत्र से विधायक हैं तथा लगातार उनकी मत प्रतिशतता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद प्रदेश के नालागढ़, हमीरपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्रों में भी महिलाओं को सम्मान निधि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस निधि को और बढ़ाया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सता में आने के पहले दिन से ही महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर ठोस प्रयास कर रहे हैं।

इस अवसर पर विधायक सुदर्शन बबलू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

बिजली उत्पादन करने वाला जिला बना ऊना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के पेखूबेला में 32 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजना के उद्घाटन अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को 500 मेगावाट सोलर ऊर्जा के दोहन का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क में ही 150 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा कि ऊना अब बिजली उत्पादन करने वाला जिला बन गया है और आने वाले समय में सौर ऊर्जा के माध्यम से यहां पर 150 मेगावाट ऊर्जा का दोहन किया जाएगा। उन्होंने पेखूबेला सौर परियोजना के शुभारंभ पर ऊना जिले के निवासियों और परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए अधिकारियों को भी बधाई दी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है और यह कदम इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राज्य सरकार प्रदूषण मुक्त विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा के दोहन के साथ-साथ सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है ताकि आने वाले समय में प्रदेश पर्यटक हब बनकर उभरे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेक विकासात्मक योजनाएं शुरू की जाएंगी।

ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण के लिए 30 जून तक चलेगा ट्रायल रन

शिमला/शैल। निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राम कुमार गौतम ने बताया कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करने के लिए 20 जून से 30 जून, 2024 तक ट्रायल रन करवाएगी। इसके अंतर्गत उचित मूल्य दुकानधारकों द्वारा राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों में से किसी एक सदस्य के आधार से जुड़े मोबाईल नम्बर पर ओटीपी भेजा जाएगा तथा उनसे मोबाईल पर सम्पर्क करके ओटीपी की जानकारी ली जाएगी।

प्रदेश में वर्तमान में कुल 1960467 राशन कार्ड धारक हैं जिनकी संख्या 7299045 है। इनमें से 99.84 प्रतिशत लोगों के आधार तथा 94.40 प्रतिशत का मोबाईल नम्बर दर्ज किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ओटीपी प्राप्त होने के बारे में जानकारी हां या न में देनी होगी तथा ओटीपी किसी भी उचित मूल्य दुकानदार या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना है। उन्होंने कहा कि इस ट्रायल का उद्देश्य भविष्य में बायोमेट्रिक सेल में किसी प्रकार की समस्या आने पर ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करने की सम्भावना को तलाशना है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार, प्रत्येक राशनकार्ड में दर्ज किसी एक व्यक्ति के मोबाईल पर ओटीपी भेज कर उस व्यक्ति से फोन पर सम्पर्क करके ओटीपी प्राप्त होने की पुष्टि करेंगे। यदि ओटीपी उपभोक्ता को प्राप्त होता है तो वे उस सदस्य की प्रविष्ट अपने पास दर्ज कर लेंगे ताकि भविष्य में राशन लेने के लिए उसके मोबाईल पर ओटीपी भेजा जा सके। यदि उस व्यक्ति के मोबाईल पर ओटीपी नहीं आता है तो उचित मूल्य दुकानधारक उसी राशन कार्ड में दर्ज किसी अन्य व्यक्ति के मोबाईल पर ओटीपी भेजेगा और ओटीपी प्राप्ति की पुष्टि होने के बाद सम्बंधित व्यक्ति का रिकार्ड अपने पास दर्ज कर लेगा।

उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे केवल ओटीपी प्राप्त होने या न होने के बारे में जानकारी उचित मूल्य दुकानधारक के साथ साझा करें और किसी भी सूरत में ओटीपी उचित मूल्य दुकानधारक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ओटीपी के माध्यम से राशन लेना चाहेगा उस स्थिति में ही राशन कार्ड ओटीपी उचित मूल्य दुकानधारक के साथ साझा करेगा।

एक्ज़िम बैंक ने मुख्यमंत्री के समक्ष हिमाचल में संभावित निर्यात रणनीति पर प्रस्तुति दी

शिमला/शैल। एक्ज़िम बैंक एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष हिमाचल प्रदेश में संभावित निर्यात रणनीति के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश फार्मास्युटिकल्स, टैक्सटाइल्स, लाइट इंजीनियरिंग, गुड्स, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों के लिए विनिर्माण हब बन गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 से राज्य का निर्यात 9,822.08 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 17,543.49 करोड़ रुपये हो गया है, जो 62 प्रतिशत वृ) को दर्शाता है। इमसें फार्मास्युटिकल्स और टैक्सटाईल प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसका प्रदेश के कुल निर्यात में 80 प्रतिशत हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को निवेश मित्र राज्य बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का निर्यात क्षेत्र में सभी राज्यों में 15वां और हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन जिला के नालागढ़ में मेडिकल डिवाईस पार्क और जिला ऊना में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक हब में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने लिए उद्यमियों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

उन्होंने राज्य का निर्यात बढ़ाने और संबंधित कमियों में सुधार के लिए दिए गए मूल्यवान सुझावों के लिए एक्ज़िम बैंक का आभार व्यक्त किया।

एक्ज़िम बैंक की प्रबन्ध निदेशक हर्षा बगनानी ने अपनी प्रस्तुति के दौरान राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय पोषण का आश्वासन दिया।

कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

एचआईवी जागरूकता के संबंध में वर्ष भर कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के निर्देश

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा शिक्षा विभाग के सभी उप-निदेशकों के लिए अभिविन्यास (ओरिएन्टेशन) बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि युवाओं और बच्चों को अगर एचआईवी के बारे में पूरी जानकारी होगी तो वह स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकेंगे।

प्रदेश के युवाओं में एचआईवी से संक्रमित होने की प्रतिशतता के मद्देनज़र राज्य एड्स नियंत्रण समिति युवाओं को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठा रही है। राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा 'व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम' के तहत 1,997 स्कूलों में 18 घंटे का पाठयक्रम शुरू किया गया है। इस पाठयक्रम के जरिए नौंवी से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को आयु अनुसार एचआईवी के विषय में विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

परियोजना निदेशक ने कहा कि 'व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम' के तहत 3,994 शिक्षकों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों में भरपूर सहयोग करें ताकि राज्य के बच्चों और युवाओं को एचआईवी और नशे के सेवन करने जैसी बुरी आदतों से बचाया जा सके। उन्होंने सभी शिक्षा उप-निदेशकों को एचआईवी के संबंध में वर्ष भर आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश भी दिए।

भाजपा को मिल रहा है हिमाचल के लोगों का आशीर्वादःजयराम

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के लोगों को पूरा सहयोग

और आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा प्रदेश में हो रहे सभी अप चुनावों को जीतेगी। प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 68 में से 61 सीटों पर पिछड़ गई। मुख्यमंत्री और ज्यादातर मंत्री अपना हलका नहीं बचा पाए। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश में कोई सरकार इतनी जल्दी अपनी लोकप्रियता खो दी हो। यह सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। किसानों, युवाओं, बागवानों के साथ धोखा किया। डेढ़ साल के कार्यकाल में प्रदेश के विकास को पूरी तरह ठप करके रखा। जनहित के मुद्दों की उपेक्षा की। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान किया। तानाशाही और बदले की भावना से काम किया। नई संस्थानों को खोलने की बजाय पहले से खुले संस्थानों को बंद किया। आज तक प्रदेश में ऐसी सरकार नहीं देखी, जिसने विकास की और जनपेक्षाओं की पूर्ण उपेक्षा की। जयराम ठाकुर ने जीएसटी काउंसिल द्वारा कार्टन पर जीएसटी घटाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि इससे बाग़वानों को बहुत राहत मिलेगी।

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार हो रहे सभी विधानसभा उपचुनाव को भाजपा जीतेगी। प्रदेश के लोग इस सरकार के कारनामों से ऊब गए हैं और सरकार को सबक़ सिखाने की तैयारी बैठे हैं। आने वाले उपचुनाव में सरकार की हर तानाशाही एयर विकास विरोधी कामों का जवाब अपने वोट से देंगे। सरकार विकास के लिए होती हैं, अस्पताल स्कूल खोलने के लिए होती हैं। सड़क, पुल, बनाने के लिए होती हैं। लेकिन यह सरकार डेढ़ साल के कार्यकाल में सड़कों का मलबा भी नहीं उठा पाई है। आपदा के पीड़ितों को अभी तक राहत नहीं दे पाई हैं। अब प्रदेश के लोग फिर से सरकार को सबक सिखायेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार तानाशाही के लिए जानी जाती है। कांग्रेस ने इमरजेंसी थोप कर देश के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा है। कल उसी काले अध्याय की बरसी है। उस दौर की यातना के बारे में देश के लोगों को जानना चाहिए।

कांग्रेस के प्रत्याशी स्थानीय नही जनता स्थानीय प्रत्याशी का देगी साथःजयराम

शिमला/शैल। भाजपा के नालागढ़ से चुनाव प्रत्याशी के एल ठाकुर की नामांकन एवं आशीर्वाद रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, सुखराम चौधरी, डॉ. सिकंदर कुमार, राजीव सैजल, बलबीर वर्मा, वीरेंद्र कश्यप परमजीत सिंह पम्मी और जिला अध्यक्ष रतन पाल सिंह उपस्थित रहे।

के.एल.ठाकुर ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के पास पैसे कहां से आते हैं उसका किसी को पता नहीं। यहां के कांग्रेस प्रत्याशी बाहर से आते हैं लोकल नहीं है और लगातार अनेकों स्थानों से पहले ही भागे हुए है, अवैध खनन, माफिया और नशा व्यापार को यह लोग संरक्षण देते हैं। ठाकुर ने कहा की हमारे संस्कार समाज सेवा के है और हम समाज सेवा करते रहेंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा की नालागढ़ की जनता भाजपा के साथ है, कांग्रेस ने केवल झूठ वायदे किया और एक भी पूरा नहीं किया। जहां जयराम सरकार के समय हिमाचल प्रदेश की जनता को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी, वह भी वापस ले ली। वर्तमान समय में महिलाओं की लंबी-लंबी लाइन कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी है जहां वह 1 लाख की मांग कर रही हैं, पर वह पैसे उनके खाते में खटाखट नहीं आये उल्टा महिलाएं खटाखट दरवाजे खटखटा रही है। हिमाचल को सौगात केवल भाजपा ने दी, अगर हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक पैकेज आया तो वह भाजपा की देन है, कांग्रेस ने तो इसको बंद करने का काम किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि इस सरकार को नया पदनाम मिल चुका है यह सरकार पति-पत्नी और मित्रों की सरकार है। यह मुख्यमंत्री केवल मित्रों के है, जब बिजली पानी देने की बात आती है तो खजाना खाली का रोना रोते हैं। पर जब कैबिनेट रैंक बांटने की बात आती है, तो केबिनेट फॉर सेल के बोर्ड लगा देते हैं। इस सरकार के पास नालागढ़ को बिजली देने के लिए नहीं है, पर रोना रोने के लिए है। इनको नालागढ़ क्षेत्र की कोई चिंता नहीं है, ऐसा एक भी काम मुख्यमंत्री गिना दे जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनमत पूरी तरह खो चुकी है, मुख्यमंत्री अपनी सीट को नही बचा पाये, मंडी लोकसभा की सीट हमने उनके हाथ से छीन ली, विधानसभा उपचुनाव में जहां कांग्रेस की 6 विधानसभा सीटें थी आज केवल 4 रह गई है। राज सत्ता तो उनके हाथ से निकलती चली जा रही है। भाजपा नालागढ़ जीतेगी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाएगी। जयराम ने कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कांग्रेस के प्रत्याशी तो यहां के रहने वाले नहीं है और यहां की जनता को यहां के रहने वाले का साथ देना चाहिए।

13 अक्तूबर 2022 को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने किया था हरोली में बनने बाले बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यासःसत्ती

शिमला/शैल। भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सत्ती ने कहा की हरोली में बनने बाले बल्क ड्रग पार्क, जिसका शिलान्यास, 13 अक्तूबर 2022 को देश के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। दोबारा उसके एक भवन व सड़क का

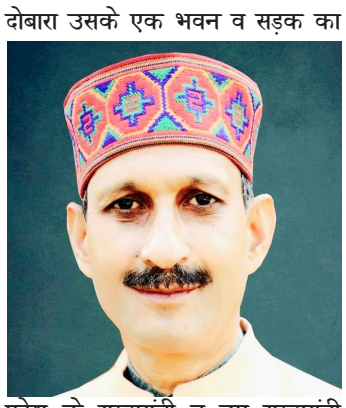

प्रदेश के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करना और उसमे केंद्र सरकार के इसी विभाग के मन्त्री जेपी नडडा को न तो आमंत्रित किया गया और न ही उन्हें ऐसा करने की जानकारी दी गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व ओछी राजनीति है।

उन्होंने कहा की स्थानीय सांसद अनुराग ठाकुर जिनका इस बल्क ड्रग पार्क को स्वीकृत करवाने में बड़ा योगदान रहा है उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया। बद्दी बरोटीवाला फार्म सैक्टर देश का ही नहीं बल्की एशिया का सबसे बड़ा हब है। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के फारमा सैक्टर के लिए रॉ मटेरियल लगभग 85% विदेशों से आता है और इसमें से भी लगभग 80% हम चीन से आयात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और केंद्र की भाजपा सरकार ने इस समस्या को समझा क्योंकि कोविड काल में तो यह स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। इसलिए जुलाई 2020 को भारत सरकार फारमा सैक्टर की कच्चे माल की दूसरे देशों पर निर्भरता ख़त्म करने के लिए देश में तीन बल्क ड्रग पार्क निर्माण करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चलने बलि तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस बल्क ड्रग पार्क का जो एकमात्र प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा वह ऊना ज़िला के हरोली का था। प्रदेश सरकार ने केंद्र के समक्ष इसका पक्ष ज़ोरदार तरीक़े से रखा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नडा और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के लिये यह प्रोजेक्ट मंजूर करवाने के लिए पूरे प्रयास किए। 30 अगस्त को केंद्र सरकार ने हिमाचल के हरोली में बनने बाले इस ड्रग पार्क को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और 11 अक्तूबर 2022 को हिमाचल की भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई DPR को अंतिम स्वीकृति भी मिल गई। 13 अक्तूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वयं ऊना आकर भारत में बनने वाले तीन बल्क ड्रग पार्कों में से एक का शिलान्यास किया। मोदी जी ने केवल शिलान्यास ही नहीं किया बल्कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाबजूद 225 करोड़ इस बल्क ड्रग पार्क के लिये लगभग ढेड़ साल पहले प्रदेश को भेजे थे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जब से बनी है एक रुपया भी इस प्रोजेक्ट को मंजूर नहीं किया। लेकिन आज राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि जो कांग्रेस के नेता मोदी सरकार द्वारा दिये जाने बल्क ड्रग पार्क का विरोध कर रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए प्रदेश के उच्च न्यायालय भेज रहे थे। आज वही नेता भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा दिये गये इस तोहफ़े का झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रहें है।

कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है : अनुराग

शिमला/शैल। भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह की नामांकन रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप में उपस्थित रहे। रैली को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा की इन उपचुनावों में भाजपा को भारी मतों से जीतना है, क्योंकि इस सोई हुई सरकार को जगाना है और बाहर का रास्ता दिखाना है। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पूरे प्रदेश में बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है। यहां का कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, साथ ही यह बैंक जनता नहीं बल्कि मित्रों के लिए बनकर रह गया है। आम आदमी को यहां लोन नहीं मिलता, पर सरकार के मित्रों को करोड़ों रुपए का लोन मिल जाता है। आम नागरिक इस सरकार में प्रताड़ित है, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी चारों सीटों पर जीत हासिल की है और इस उपचुनाव में भी हम तीनों सीट पर जीत दर्ज करेगे। ठाकुर ने कहा की यह लड़ाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है।

जयराम ठाकुर ने कहा की यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यक्रम जहां सभा स्थल पर होना चाहिए था आज सड़कों पर हो रहा है। मुख्यमंत्री इस चुनाव को सत्ता के दबाव में लड़ना चाहती हैं, पर भाजपा रुकने वाली नहीं है। आप जितना भी दबाव डाल लो हम चुनाव दम से लड़ेंगे। इस सरकार ने तो हमें रैली के लिए सभा स्थल तक नहीं दिया।

उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री बार-बार पूछते हैं कि यह उपचुनाव क्यों हो रहे हैं? हम उनको बताना चाहेंगे की यह चुनाव आपकी वजह से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का स्वभाव विधायकों को साथ लेकर चलने का है ही नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री को इन विधायकों ने बाय-बाय कह दिया। मुख्यमंत्री जी आपके विधायक आपसे समय मांगते रहे, आपने उनको समय तक नहीं दिया। इन विधायकों का इस्तीफा देने में कोई दोष नहीं है दोष तो केवल आपका है। राज्यसभा चुनाव में अपने राम विरोधी को टिकट दे दी, बहुमत होने के बावजूद आप हार गये और भाजपा जीत गई। यह सभी विधायक हिम्मत वाले हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, अगर देहरा के लिए कोई लड़ सकता है तो वह केवल होशियार सिंह है जब हमारी सरकार थी तो यह अपनी मांगों के लिए लड़कर विकास कार्यो के लिए 150 करोड रुपए ले गए थे और अपने कांग्रेस सरकार के समय देहरा को 1 : तक नहीं दिया।

होशियार सिंह ने कहा कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से ग्रस्त है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री दोषारोपण की राजनीति कर रहे है वह गलत है। कांग्रेस सरकार के समय गुंडागर्दी का बोलबाला है और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी पर रही है उसे साफ प्रतीत होता है कि यह सरकार गुंडो की सरकार है।

हर मण्डल में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसःकटवाल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने बताया की जैसा कि हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों से 21 दिसम्बर, 2014 को

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 193 सदस्य देशों के समर्थन से 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल के निर्देशानुसार इस वर्ष भी विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रत्येक मण्डल में योग के कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए सभी जिलाध्यक्ष, जिला संयोजक व मण्डल अध्यक्ष अपने-अपने मण्डल में इस कार्यक्रम के संयोजक होंगे। इस योग दिवस के कायक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंडल में 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा की सभी भाजपा नेता, 2022 के प्रताशी, अपने अपने मंडलों में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।

संजीव कटवाल ने कहा की भाजपा समस्त किसानों की ओर से पीएम मोदी का किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करने ले लिए धन्यवाद भी करती है।

पीएम मोदी ने देश के 9.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में डीबीटी के जरिये 20 हज़ार करोड़ रुपये अंतरित किए। उन्होंने कहा कि तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की तरफ भी पीएम ने बड़े कदम उठाए है। उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित किए जाएंगे।

कटवाल ने कहा कि किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कृषि निर्यात में देश अग्रणी बना है।

कटवाल ने कहा की कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में आयी है तब से केवल मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और अब तो परिवारवाद भी पनपता दिखाई दे रहा है, देहरा से सीएम ने अपनी पत्नी को ही टिकट दे दी और चर्चा का विषय तो यह है कि एक दिन पहले सीएम और उनकी पत्नी दोनो मना कर रहे थे कि यह टिकट मुझे और मेरी पत्नी को नहीं मिलेगी। अब बड़ी जल्द हिमाचल सरकार के सभी मित्र देहरा विधानसभा क्षेत्र में पाये जाएंगे, झूठ बोलने और सत्ता का दुरुपयोग करने में तो सीएम और उनके मित्र वैसे ही मास्टर है। देहरा को जिला बनाएंगे नोटिफिकेशन बाद में आएगी इस प्रकार की चुनावी स्टंट हमें देखने को मिल भी रहे हैं और आगे और भी मिलेंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

यदि मुख्य संसदीय सचिवों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा तो भाजपा के नौ लोग भी बाहर जाएंगे

- चुनाव आचार संहिता के चलते देहरा को मिला पुलिस जिला और लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय
- कमलेश ठाकुर के चुनावी शपथ पत्र पर होशियार सिंह ने उठाये सवाल एसडीएम को दी शिकायत

शिमला/शैल। लोकसभा चुनाव से लेकर अब इन उपचुनाव तक विपक्ष और सत्ता पक्ष में सरकार के गिरने को लेकर जो दावों प्रतिदावों का खेल चल रहा है वह अब मुख्य संसदीय सचिवों और भाजपा के नौ विधायकों के संभावित निष्कासन तक पहुंच गया है। मुख्य संसदीय सचिवों का मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है। यह मामला उच्च न्यायालय में इस आधार पर पहुंचा है कि संसद में हुये 91वें संविधान संशोधन में हर सरकार में केंद्र से लेकर राज्यों तक मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इस संशोधन के मुताबिक हिमाचल में मंत्रियों की संख्या बारह ही हो सकती है। लेकिन इस संशोधन के प्रभाव को कम करने के लिये राज्यों की कई सरकारों ने अपने-अपने एक्ट पास करके संसदीय सचिवों के पद सृजित कर रखे हैं जो व्यवहारिक तौर पर मंत्रियों के ही समकक्ष प्रभावशाली हो गये हैं। हिमाचल में स्व. वीरभद्र सिंह के शासनकाल में मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की गई थी। इन नियुक्तियों को सिटीजन प्रोटेक्शन फॉरम के अध्यक्ष देशबंधु सूद ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया और यह लोग हट गये। उसके बाद सरकार ने इस मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर दी और साथ ही इस आश्य का नया कानून भी पारित कर दिया। प्रदेश के कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती मिली हुई है जिस पर फैसला संभावित है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल की अपील असम के मामले के साथ संबद्ध हो गई और फैसला आ गया कि राज्य विधायिका इस तरह का कानून पारित करने के लिये सक्षम ही नहीं है। इस पृष्ठभूमि में यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है और कभी भी फैसला आ सकता है। भाजपा इस मामले को ऐसे प्रचारित कर रही है की मुख्य संसदीय सचिवों को संभावित फैसले में सदन से बाहर होना पड़ेगा। बाहर होने की स्थिति में इनके संस्थानों पर भी उपचुनाव की नौबत आ जायेगी। लेकिन यह सब उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। परन्तु इस संभावना का जवाब सरकार की ओर से इस तर्ज पर दिया जा रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के नौ विधायकों के खिलाफ भी निष्कासन की कारवाई को अंजाम दे दिया जायेगा। स्मरणीय है कि राज्यसभा का चुनाव हार जाने के बाद ही कांग्रेस के बागियों को सदन से बाहर किया गया था। उसी के प्रतिफल के रूप में निर्दलीयों के स्थान पर अब उप चुनाव हो रहे हैं। उसी चुनाव के दौरान भाजपा विधायकों पर असंसदीय आचरण का आरोप लगा और इस मामले में कारवाई विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। ऐसा लगता है कि यदि मुख्य संसदीय सचिवों को सदन से बाहर जाना पड़ा तो भाजपा के लोगों के खिलाफ चल रहे मामले में भी उनको बाहर का रास्ता दिखाकर उनके स्थानों पर भी उपचुनाव की नौबत आ जायेगी। यह स्पष्ट संकेत दिया जा रहा है कि यदि संसदीय सचिवों को बाहर जाने की नौबत आयी तो भाजपा के नौ लोगों को भी बाहर कर दिया जायेगा। आज प्रदेश की राजनीति इस मुकाम पर पहुंच चुकी है।

देहरा में उपचुनाव हो रहा है और आदर्श आचार संहिता लागू है। आचार संहिता के चलते मंत्रिपरिषद द्वारा देहरा को पुलिस जिला बनाने का फैसला आना और लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता का कार्यालय खोलने का फैसला लेना आचार संहिता की अहवेलना है। लेकिन इन फैसलों पर भाजपा की ओर से कोई सार्वजनिक ब्यान नहीं आया है। केवल चुनाव आयोग को शिकायत भेजने की औपचारिकता निभाकर शान्त होकर बैठ गये हैं यही नहीं देहरा से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर को चुनाव में उतारा है। चुनाव में कमलेश ठाकुर द्वारा दायर किये गये शपथ पत्र पर भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने कुछ एतराज उठाते हुए इस संबंध में सबद्ध अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन इस शिकायत के तथ्यों पर भाजपा द्वारा कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। देहरा में भाजपा को रैली की अनुमति देकर बाद में उसे रद्द कर दिया गया। भाजपा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करके एसडीएम देहरा के तुरन्त स्थानांतरण की मांग की थी। लेकिन शिकायत की औपचारिकता निभा कर चुप बैठ जाना एक अलग ही कहानी बयां करता है। इस परिदृश्य में मुख्य संसदीय सचिवों और भाजपा के नौ विधायकों के खिलाफ कारवाई की चर्चाएं केवल जनता का ध्यान आकर्षित करने की औपचारिकता से अधिक कुछ भी नहीं माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की पत्नी के प्रत्याशी होने के कारण देहरा का वातावरण ऊपर से जितना शान्त दिखाई दे रहा है अन्दर से उतना ही विस्फोटक होने की कगार पर पहुंच रहा है।

यदि इनके त्यागपत्र पहले ही स्वीकार

.....पृष्ठ 1 का शेष

के लिये कांग्रेस सरकार और संगठन के रिश्तों और इसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। स्मरणीय है कि सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालते ही अपने शासन का मूल सूत्र व्यवस्था परिवर्तन जनता को परोसा। इस सूत्र के तहत प्रशासन के शीर्ष से लेकर नीचे तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो प्रशासन भाजपा शासन काल में फील्ड में प्रभावी चल रहा था नई सरकार में भी वही यथास्थिति बन रहा है। इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को सरकार के साथ नहीं जोड़ पाया। भाजपा शासन के अंतिम छः माह के फैसले बदलते हुये करीब एक हजार नये खोले गये कार्यालय बन्द कर दिए गये और भाजपा को पहले पखवाड़े में ही विरोध प्रदर्शन का मुद्दा थमा दिया। भाजपा मन्त्रीमंडल के विस्तार से पहले ही प्रदेशभर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर आ गयी। सरकार ने यह संस्थान बंद करने के लिये प्रदेश की नाजुक वित्तीय स्थिति का तर्क जनता के सामने रखा। यहां तक बताया कि प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। तुरंत प्रभाव से डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिया। जनता को लगा कि शायद सही में प्रदेश की वित्तीय स्थिति नाजुक है। लेकिन इस धारणा को तब पहले धक्का लगा जब मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही छः मुख्य संसदीय सचिवों को मुख्यमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी। फिर मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय असंतुलन सामने आ गया। मंत्रियों के तीन पद खाली रखे गये। लेकिन इसी के साथ सरकार में गैर विधायकों में से विशेष कार्यअधिकारी और सलाहकारों के इतने पद भर दिए जो शायद संख्या में मंत्रियों से भी अधिक हो गये। अधिकांश को कैबिनेट का दर्जा देना पड़ा। इसमें भी जिला शिमला की भागीदारी ज्यादा हो गयी। इस सब का असर यह हुआ कि संगठन और सरकार में तालमेल का अभाव उभरने लगा। इस तालमेल के अभाव के आरोपों को लेकर हाईकमान तक शिकायतें पहुंची। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे राजेन्द्र राणा को खुले पत्र लिखने पड़ गये। सरकार के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के शिकायत पत्र वायरल हो गये। संगठन और सरकार में तालमेल न होने की शिकायतें स्वयं पार्टी अध्यक्षा ने हाईकमान के सामने रखी। इसी तालमेल के अभाव की व्यवहारिक सच्चाई के चलते पार्टी अध्यक्षा को यहां तक कहना पड़ा कि लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता फील्ड में नहीं निकलेगा। स्वयं सांसद का चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया जबकि जयराम सरकार में उपचुनाव में उन्होंने यह सीट जीती थी। जब सरकार और संगठन में तालमेल के अभाव के आरोप इस स्तर पर मुखर हो जाये और हाईकमान अपने ही कारणों से ऐसी शिकायतों पर कारवाई न कर पाये तो ऐसी वस्तुस्थिति का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जब मंत्रिपरिषद का विस्तार करके दो मंत्रियों को शामिल किया गया तो उनको विभागों का आवंटन करने में ही इतना समय लगा दिया गया जो उनके धैर्य और आत्म सम्मान की परीक्षा के मुकाम तक पहुंच गया। हिमाचल के लिये हाई कमान गौण होकर रह गई क्योंकि समन्वय कमेटी भी कागजी गठन होकर रह गयी। ऐसी वस्तु स्थिति में कौन आदमी ऐसी व्यवस्था से जुड़ना चाहेगा। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जब पार्टी के अपने ही विधायकों के खुले रोष का संज्ञान नहीं लिया जायेगा तो अपने आत्म सम्मान की कीमत पर कोई विधायक पार्टी नेतृत्व के साथ चल पायेगा। कांग्रेस के बागियों ने अपने रोष को मुखर करने के लिये राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने का निर्णय लिया। जब कांग्रेस के अपने ही विधायक इस सीमा तक उपेक्षित महसूस करने लग गये थे तो निर्दलीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मसलों के हल होने के लिये सरकार पर कितना भरोसा कर सकते थे। क्योंकि वह तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। इसलिए आज इन उपचुनावों के लिये निर्दलीयों को ही दोषी ठहराना गलत होगा। यदि सत्ता पक्ष अपनी राजनीतिक चालों से ऊपर उठकर निर्दलीयों के त्यागपत्र स्वीकार होने देता और यह चुनाव भी साथ ही हो जाते। तब सत्ता पक्ष का सवाल ज्यादा भारी पड़ता। इस समय इन उपचुनावों के लिये विधायकों के बिकने और भाजपा के धन बल प्रयोग का आरोप अपने में ही तर्कहीन हो जाता है क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में हार चुकी है। लोकसभा चुनावों में जो वोट शेयर बढ़ाने का दावा किया जा रहा है उसका सच यह है कि इस चुनाव में विपक्षी एकता के नाम पर वामदल सरकार के साथ खड़े थे और प्रदेश में उनका अपना इतना आधार मौजूद है।

क्या यह उपचुनाव मुद्दों

.....पृष्ठ 1 का शेष

रूप में और हथियार उपलब्ध हो गये हैं। जबकि इस समय के सबसे बड़े मुद्दे हैं कि यह सरकार कितना कर्ज लेकर चुनावी गारंटीयां पूरी कर पायेगी? क्योंकि हर माह कर्ज लेना पड़ रहा है। संसाधन बढ़ाने के लिये लगाया गया वाटर सैस कानूनी दाव पेंच में उलझ गया है। विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी बढ़ाने का प्रयास भी अदालत में सफल नहीं हो पाया है। युवाओं को रोजगार उपलब्धता भाषणों से आगे नहीं बढ़ पायी है। ओपीएस के कारण पैन्शन में कटौती करने की संभावनाएं चर्चा में आ गयी हैं। इन मुद्दों पर खुली बहस की आवश्यकता है क्योंकि उपचुनाव में हार जीत से सरकार और विपक्ष के भविष्य पर कोई बड़ा अन्तर पढ़ने वाला नहीं है।